myresearchgo Volume 2, Issue 6, June 2026, ISSN: 3107-3816 (Online)

टोंक जिले में जनसंख्या, श्रमशक्ति और औद्योगिक विकास के अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन

(A Study of the Interrelationships among Population, Labour Force and Industrial Development in Tonk District)

डॉ. विष्णु चौधरी

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित टोंक जिले में जनसंख्या, श्रमशक्ति और औद्योगिक विकास के मध्य पाए जाने वाले अन्तर्सम्बन्धों का स्थानिक एवं आर्थिक-भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन की पृष्ठभूमि इस तथ्य में निहित है कि जनसंख्या केवल उपभोक्ता वर्ग ही नहीं, अपितु श्रमशक्ति की आपूर्ति तथा स्थानीय उपभोक्ता बाजार दोनों के रूप में औद्योगिक स्थानिकी को प्रभावित करती है। टोंक जिला, जो जयपुर और अजमेर जैसे विकसित नगरीय-औद्योगिक केन्द्रों के मध्य अवस्थित होने के बावजूद वर्ष 2006 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश के 250 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में सम्मिलित किया गया, इस अन्तर्सम्बन्ध के अध्ययन हेतु एक उपयुक्त भौगोलिक प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जिले की जनसंख्या संरचना, श्रमशक्ति की संरचनात्मक विशेषताओं और औद्योगिक विकास के स्थानिक प्रतिरूप का परीक्षण करना तथा इनके पारस्परिक संबंध की प्रकृति को स्पष्ट करना है। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों विशेषकर भारत की जनगणना 2011, टोंक जिले की संक्षिप्त औद्योगिक रूपरेखा (DCMSME) तथा RIICO के अभिलेखों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का अनुसरण करता है।

प्रमुख निष्कर्ष यह है कि जिले में जनसंख्या वृद्धि (2001–2011 में लगभग 17.33 प्रतिशत) तथा प्रचुर ग्रामीण श्रमशक्ति की उपलब्धता के अनुपात में औद्योगिक विकास सीमित एवं चयनित नगरीय-परिवहन गलियारों तक केन्द्रित रहा है। अध्ययन यह स्थापित करता है कि कृषि-प्रधान श्रमशक्ति का गैर-कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की ओर समुचित अंतरण न होने के कारण उपलब्ध मानव संसाधन का अपूर्ण उपयोग हो रहा है, जिससे प्रवास तथा क्षेत्रीय असमानता को बल मिलता है। भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन संतुलित एवं विकेन्द्रित औद्योगिक विकास मॉडल की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द (Keywords)

जनसंख्या भूगोल, श्रमशक्ति संरचना, औद्योगिक स्थानिकी, टोंक जिला, आर्थिक भूगोल, क्षेत्रीय असमानता, कार्य सहभागिता दर

प्रस्तावना (Introduction)

जनसंख्या और उद्योग के बीच का संबंध आर्थिक भूगोल की केन्द्रीय समस्याओं में से एक है। शास्त्रीय औद्योगिक स्थानिकी सिद्धांतों में जहाँ कच्चे माल, परिवहन-लागत और बाजार की भूमिका को प्रमुखता दी गई, वहीं आधुनिक प्रादेशिक विकास अध्ययनों में जनसंख्या को द्विमुखी कारक के रूप में देखा जाता है एक ओर वह श्रमशक्ति (उत्पादन कारक) की आपूर्ति करती है और दूसरी ओर उपभोक्ता बाजार (मांग कारक) का निर्माण करती है। इस प्रकार जनसंख्या न तो केवल भार है और न ही केवल संसाधन; उसकी आर्थिक भूमिका इस बात से निर्धारित होती है कि उपलब्ध श्रमशक्ति का उत्पादक क्षेत्रों में किस सीमा तक उपयोग हो पाता है।

औद्योगिक गतिविधियाँ अपने पीछे रोजगार सृजन, ग्रामीण-नगरीय प्रवास, नगरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा व्यापक सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण की एक श्रृंखला छोड़ती हैं। जहाँ औद्योगिक आधार सशक्त होता है, वहाँ जनसंख्या आर्थिक संपदा में रूपांतरित होती है; और जहाँ औद्योगिक आधार दुर्बल रहता है, वहीं वही जनसंख्या बेरोजगारी, अल्परोजगार और बहिर्गामी प्रवास का स्रोत बन जाती है। भूगोल के परिप्रेक्ष्य में इन प्रक्रियाओं का विश्लेषण जनसंख्या वितरण, संसाधन आधार, परिवहन सुगम्यता, बाजार सामीप्य और श्रम उपलब्धता के स्थानिक प्रतिरूपों के माध्यम से किया जाता है।

राजस्थान का औद्योगिक मानचित्र स्पष्ट क्षेत्रीय असमानता प्रदर्शित करता है। जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, कोटा और अजमेर जैसे जिले अपेक्षाकृत विकसित औद्योगिक केन्द्रों के रूप में उभरे हैं, जबकि अनेक जिले अब भी कृषि-प्रधान एवं औद्योगिक रूप से पिछड़े बने हुए हैं। टोंक जिला इसी दूसरी श्रेणी का प्रतिनिधि उदाहरण है। जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित होने तथा बीसलपुर बाँध जैसे जल-स्रोत से जुड़ा होने के बावजूद, यह जिला मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर रहा है और इसकी औद्योगिक संरचना लघु, कुटीर तथा कृषि-आधारित इकाइयों तक सीमित है (Brief Industrial Profile of Tonk District, MSME-DI, Government of India)। यह विरोधाभास अनुकूल अवस्थिति बनाम सीमित औद्योगिकीकरण ही इस अध्ययन का केन्द्रीय प्रश्न है: यदि श्रमशक्ति और बाजार दोनों उपलब्ध हैं, तो औद्योगिक विकास सीमित क्यों है, और जनसंख्या-श्रमशक्ति-उद्योग की त्रिवेणी किस प्रकार परस्पर क्रियाशील है?

अध्ययन क्षेत्र का परिचय: टोंक जिला (The Study Area)

टोंक जिला राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में, अजमेर संभाग के अंतर्गत अवस्थित है। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार यह जिला लगभग 75°07’ से 76°19’ पूर्वी देशांतर तथा 25°41’ से 26°34’ उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है (Brief Industrial Profile of Tonk District, MSME-DI)। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 7,194 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे मध्यम श्रेणी में रखता है। जिला उत्तर में जयपुर, पूर्व में सवाई माधोपुर, दक्षिण-पूर्व में कोटा, दक्षिण में बूँदी, दक्षिण-पश्चिम में भीलवाड़ा तथा पश्चिम में अजमेर जिले से घिरा है (Tonk district, census-आधारित)।

प्रशासनिक दृष्टि से जिले में सात उपखंड तथा परंपरागत रूप से सात तहसीलें टोंक, मालपुरा, निवाई, देवली, उनियारा, टोडारायसिंह और पीपलू रही हैं, जिनमें कालांतर में दूनी एवं नगरफोर्ट जैसी नई तहसीलें जोड़ी गईं (Tonk district)। प्रमुख नगरीय केन्द्रों में टोंक (जिला मुख्यालय एवं नगर परिषद), तथा देवली, निवाई, मालपुरा, टोडारायसिंह और उनियारा (नगर पालिकाएँ) सम्मिलित हैं।

भौतिक संरचना की दृष्टि से जिला सामान्यतः समुद्रतल से लगभग 214 मीटर की औसत ऊँचाई पर अवस्थित एक समतल मैदान है, जिसमें कहीं-कहीं अरावली प्रणाली से संबद्ध पथरीली पहाड़ियाँ उभरती हैं। मृदा प्रायः उपजाऊ किन्तु कुछ बलुई प्रकृति की है और उपभू-जल सीमित है (MSME-DI, Tonk)। जलवायु अर्ध-शुष्क है; औसत वार्षिक वर्षा लगभग 61–62 सेंटीमीटर है, जिसका लगभग 93 प्रतिशत भाग जून से सितम्बर के मानसून काल में प्राप्त होता है।

जल संसाधन की दृष्टि से बनास नदी जिले की जीवन-रेखा है। यह नदी देवली तहसील के नेगड़िया से जिले में प्रवेश करती है और सर्पाकार मार्ग से बहती हुई जिले को विभाजित करती है; मानसी, सोहादरा, खारी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। देवली के समीप निर्मित बीसलपुर बाँध न केवल जयपुर एवं अजमेर को पेयजल उपलब्ध कराता है, अपितु देवली, टोंक एवं उनियारा तहसीलों में सिंचाई एवं उपभू-जल स्तर को भी प्रभावित करता है (MSME-DI, Tonk)। खनिज संसाधनों में स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज़, फेल्सपार, सिलिका रेत और गार्नेट की उपस्थिति जिले को संसाधन-आधारित लघु उद्योगों का सीमित आधार प्रदान करती है।

परिवहन की दृष्टि से जिला राष्ट्रीय राजमार्ग (पूर्ववर्ती NH-12, वर्तमान NH-52 के रूप में संदर्भित) पर अवस्थित है और सड़क मार्ग से जयपुर एवं अजमेर से जुड़ा है। तथापि एक उल्लेखनीय भौगोलिक सीमा यह है कि जिला मुख्यालय टोंक राज्य के उन गिने-चुने जिला मुख्यालयों में से एक है जो प्रत्यक्ष रेल संपर्क से वंचित हैं; निकटतम रेलवे स्टेशन निवाई जिले के भीतर ही है किन्तु मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है (Tonk district,)। यह तथ्य औद्योगिक स्थानिकी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेल-संपर्क का अभाव भारी एवं वृहत्-स्तरीय उद्योगों के स्थानन को हतोत्साहित करता है। इस प्रकार जिला अनुकूल अवस्थिति (जयपुर-अजमेर अक्ष के मध्य) तथा अवसंरचनात्मक सीमाओं (रेल अभाव, सीमित उपभू-जल) के बीच एक संक्रमणकालीन औद्योगिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व (Need and Significance)

टोंक जिले में जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है तथा ग्रामीण श्रमशक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु यह श्रमशक्ति मुख्यतः कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। ऐसी स्थिति में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या वृद्धि एवं श्रम-आपूर्ति का औद्योगिक विकास से क्या संबंध है, और क्यों उपलब्ध मानव संसाधन उत्पादक औद्योगिक रोजगार में रूपांतरित नहीं हो पा रहा। कृषि-आधारित श्रमशक्ति की अधिकता एक ओर भूमि पर अत्यधिक दबाव तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी को जन्म देती है, और दूसरी ओर यह औद्योगिक क्षेत्र की ओर श्रम-अंतरण की संभावना भी प्रस्तुत करती है।

इस अध्ययन का महत्व बहुस्तरीय है। नीतिगत दृष्टि से यह जिला औद्योगिक योजना, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय संतुलन की रणनीतियों के लिए आधार-सामग्री प्रदान कर सकता है, विशेषकर इसलिए कि टोंक पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) प्राप्त करने वाले राजस्थान के जिलों में सम्मिलित रहा है (Ministry of Panchayati Raj, 2009)। स्थानीय औद्योगिक विकास से रोजगार सृजन, बहिर्गामी प्रवास पर नियंत्रण, आय-वृद्धि तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी संभव है। अकादमिक दृष्टि से यह अध्ययन जनसंख्या भूगोल और औद्योगिक भूगोल के अंतर्संबंध को राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय सामान्यीकरण के स्थान पर एक सूक्ष्म-प्रादेशिक (जिला) स्तर पर स्पष्ट करता है, जहाँ स्थानिक प्रक्रियाओं की वास्तविक झलक अधिक स्पष्टता से देखी जा सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. टोंक जिले की जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व के स्थानिक प्रतिरूप का अध्ययन करना।
2. जिले की श्रमशक्ति संरचना, कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या तथा कार्य सहभागिता दर का विश्लेषण करना।
3. टोंक जिले में औद्योगिक विकास की प्रकृति, स्थिति एवं स्थानिक वितरण का परीक्षण करना।
4. जनसंख्या, श्रमशक्ति और औद्योगिक विकास के मध्य अन्तर्सम्बन्धों की प्रकृति की जाँच करना।
5. औद्योगिक विकास में श्रम उपलब्धता, बाजार, परिवहन एवं नगरीकरण की भूमिका का विश्लेषण करना।
6. जिले में औद्योगिक विकास की चुनौतियों एवं संभावनाओं की पहचान करना।
7. संतुलित एवं विकेन्द्रित क्षेत्रीय विकास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनाएँ (Hypotheses)

अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं:

1. टोंक जिले में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में औद्योगिक विकास पर्याप्त नहीं हुआ है।
2. जिले में श्रमशक्ति की उपलब्धता पर्याप्त है, परन्तु उसका औद्योगिक क्षेत्र में समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।
3. औद्योगिक इकाइयों का वितरण नगरीय एवं परिवहन-सुगम क्षेत्रों (टोंक, निवाई, देवली) में अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रित है।
4. कृषि-प्रधान श्रमशक्ति की प्रधानता के कारण जिले में औद्योगिक विविधीकरण की आवश्यकता अधिक है।
5. कौशल विकास, आधारभूत संरचना एवं निवेश में वृद्धि होने पर जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।

शोध पद्धति (Research Methodology)

अध्ययन की प्रकृति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक प्रकृति का है। इसमें जनसांख्यिकीय एवं औद्योगिक तथ्यों का वर्णन, उनके स्थानिक प्रतिरूपों का विश्लेषण तथा जनसंख्या-श्रम-उद्योग के अन्तर्सम्बन्धों की कारणात्मक व्याख्या सम्मिलित है।

आँकड़ों के स्रोत

अध्ययन मुख्यतः **द्वितीयक स्रोतों** पर आधारित है, जिनमें भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 तथा टोंक हेतु जिला जनगणना पुस्तिका (District Census Handbook, Tonk), टोंक जिले की संक्षिप्त औद्योगिक रूपरेखा (Brief Industrial Profile of Tonk District, MSME Development Institute, भारत सरकार), राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग एवं जिला उद्योग केन्द्र, टोंक के अभिलेख, RIICO (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) की औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सूचना तथा राजस्थान आर्थिक समीक्षा एवं सांख्यिकीय सार जैसे सरकारी प्रकाशन सम्मिलित हैं।

जहाँ गहन क्षेत्रीय सत्यापन वांछित हो, वहाँ **प्राथमिक स्रोतों** चयनित औद्योगिक इकाइयों के सर्वेक्षण, उद्यमियों एवं श्रमिकों के साक्षात्कार तथा औद्योगिक क्षेत्रों के क्षेत्रीय निरीक्षण का उपयोग पूरक रूप में किया जा सकता है। प्रस्तुत विश्लेषण में जहाँ तहसील-वार सूक्ष्म आँकड़े प्रकाशित स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित नहीं हैं, वहाँ ''उपलब्ध नवीनतम स्रोतों के आधार पर'' अथवा ''अनुमानात्मक विश्लेषण'' के रूप में स्पष्ट संकेत दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रामाणिक संख्या का समावेश न हो।

विश्लेषण की विधियाँ

विश्लेषण में प्रतिशत विश्लेषण, दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व की गणना, कार्य सहभागिता दर (Work Participation Rate), मुख्य एवं सीमांत श्रमिकों का तुलनात्मक विश्लेषण, ग्रामीण-नगरीय तुलना तथा औद्योगिक इकाइयों के स्थानिक वितरण का परीक्षण सम्मिलित है। तथ्यों की प्रस्तुति हेतु तालिकाओं, ग्राफों एवं स्थानिक प्रतिरूप-विवरणों का प्रयोग किया गया है, तथा आवश्यकतानुसार जनसंख्या/श्रम चरों एवं औद्योगिक चरों के मध्य गुणात्मक सहसम्बन्धात्मक व्याख्या की गई है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

औद्योगिक स्थानिकी के अध्ययन की सैद्धांतिक नींव अल्फ्रेड वेबर (Alfred Weber) के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत (Theory of Industrial Location, 1909) में निहित है, जिसमें परिवहन-लागत, श्रम-लागत तथा समूहन (agglomeration) कारकों के आधार पर न्यूनतम-लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रस्तुत की गई। यह सिद्धांत टोंक जैसे जिले के संदर्भ में प्रासंगिक है, क्योंकि यहाँ रेल-संपर्क का अभाव एवं सीमित परिवहन-सुगम्यता परिवहन-लागत को बढ़ाकर भारी उद्योगों को हतोत्साहित करते हैं; तथापि वेबर का मॉडल बाजार-मांग एवं शासकीय नीति जैसे आधुनिक कारकों को अपेक्षाकृत कम महत्व देता है, जो इसकी एक सीमा है।

अगस्त लॉश (August Lösch) के बाजार-क्षेत्र सिद्धांत तथा क्रिस्टॉलर के केन्द्रीय स्थान सिद्धांत (Central Place Theory) नगरीय केन्द्रों के बाजार-प्रभाव-क्षेत्र को समझने में सहायक हैं और यह व्याख्या करते हैं कि टोंक, निवाई एवं देवली जैसे कस्बे क्यों स्थानीय औद्योगिक-सेवा केन्द्रों के रूप में उभरते हैं। जनसंख्या भूगोल एवं आर्थिक भूगोल की मानक रचनाएँ जैसे आर. सी. चांदना की *Population Geography* तथा आर. एल. सिंह व अन्य भारतीय भूगोलवेत्ताओं के कार्य श्रमशक्ति संरचना, कार्य सहभागिता और जनसंख्या-संसाधन संबंध की वैचारिक रूपरेखा प्रदान करती हैं।

राजस्थान के औद्योगिक विकास एवं क्षेत्रीय असमानता पर हुए विभिन्न शोध अध्ययन यह दर्शाते हैं कि राज्य में औद्योगिकीकरण कुछ चयनित गलियारों (जयपुर-अलवर, भीलवाड़ा, कोटा) तक केन्द्रित रहा है, जबकि अनेक मध्यवर्ती जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े बने रहे एक प्रवृत्ति जिसकी पुष्टि टोंक के पिछड़े जिलों में सम्मिलन से होती है। श्रम-प्रवास, नगरीकरण एवं ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार पर केंद्रित अध्ययन यह स्थापित करते हैं कि स्थानीय औद्योगिक आधार की अनुपस्थिति में ग्रामीण श्रमशक्ति विकसित नगरीय केन्द्रों की ओर पलायन करती है।

इन अध्ययनों की सामूहिक उपयोगिता यह है कि वे एक सैद्धांतिक एवं तुलनात्मक ढाँचा प्रदान करते हैं; किन्तु इनकी प्रमुख सीमा यह है कि अधिकांश राज्य-स्तरीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर केंद्रित हैं और टोंक जिले को विशेष रूप से जनसंख्या-श्रम-उद्योग के अन्तर्सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। प्रस्तुत शोध इसी शोध-रिक्तता (research gap) को संबोधित करता है।

जनसंख्या संरचना का विश्लेषण (Population Structure)

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार टोंक जिले की कुल जनसंख्या **1,421,326** थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसे जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 347वें स्थान पर रखती है (District Census Handbook, Tonk, Census of India 2011)। जिले का जनसंख्या घनत्व लगभग **198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर** रहा, जो राज्य के औसत से कम है और जिले की अर्ध-ग्रामीण, कृषि-प्रधान बसावट प्रकृति को दर्शाता है।

दशकीय वृद्धि के संदर्भ में, 2001 से 2011 के दशक में जिले की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग **17.33 प्रतिशत** रही, जो राजस्थान राज्य की दशकीय वृद्धि दर (लगभग 21.31 प्रतिशत) से स्पष्ट रूप से कम है (Census of India 2011; District Profile Tonk)। दीर्घकालिक प्रवृत्ति पर दृष्टि डालें तो जिले की जनसंख्या 2001 में 1,211,671 से बढ़कर 2011 में 1,421,326 हो गई, अर्थात पूर्ववर्ती दशकों (जिनमें वृद्धि दर प्रायः 20 प्रतिशत से अधिक रही थी) की तुलना में वृद्धि की गति में मंदी आई है।

नगरीकरण की दृष्टि से जिले की केवल लगभग **22.35 प्रतिशत** जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, अर्थात लगभग तीन-चौथाई से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है (Census of India 2011)। यह निम्न नगरीकरण स्तर एक ओर सशक्त औद्योगिक-नगरीय केन्द्रों के अभाव को इंगित करता है और दूसरी ओर इस तथ्य को रेखांकित करता है कि औद्योगिक विकास का प्रमुख संभावित आधार ग्रामीण एवं अर्ध-नगरीय श्रमशक्ति ही है।

लिंगानुपात की दृष्टि से जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग **949 स्त्रियाँ** थीं; उल्लेखनीय है कि टोंक का नगरीय लिंगानुपात (लगभग 982–985) राज्य में सर्वाधिक में से एक रहा है (Census of India 2011; testbook/rajras स्रोत)। साक्षरता दर लगभग **62.46 प्रतिशत** रही, जिसमें पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच उल्लेखनीय अंतराल विद्यमान है (महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता की तुलना में काफी कम है, यद्यपि सटीक लिंग-वार प्रतिशत हेतु जिला जनगणना पुस्तिका के मूल आँकड़े देखे जाने चाहिए)। निम्न साक्षरता, विशेषकर निम्न महिला साक्षरता, कुशल श्रमशक्ति के निर्माण में एक संरचनात्मक बाधा है।

सामाजिक संरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या लगभग **20.26 प्रतिशत** तथा अनुसूचित जनजाति (ST) की जनसंख्या लगभग **12.54 प्रतिशत** रही (Census of India 2011)। यह अपेक्षाकृत उच्च अनुपात कौशल विकास एवं समावेशी औद्योगिक रोजगार नीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

तहसील/ब्लॉक-वार वितरण की दृष्टि से जनसंख्या का संकेन्द्रण मुख्यतः टोंक मुख्यालय तथा निवाई जैसे परिवहन-सुगम केन्द्रों के समीप अधिक है, जबकि उनियारा एवं टोडारायसिंह जैसे क्षेत्रों में बसावट अपेक्षाकृत विरल है (अनुमानात्मक स्थानिक प्रवृत्ति; तहसील-वार सटीक संख्या हेतु District Census Handbook, Tonk का मूल आँकड़ा अपेक्षित)।

समग्र रूप से जनसंख्या संरचना एक द्विधारी निहितार्थ प्रस्तुत करती है: एक ओर बड़ी एवं युवा ग्रामीण जनसंख्या प्रचुर श्रमशक्ति एवं उपभोक्ता बाजार प्रदान करती है, जो औद्योगिक विकास का आधार बन सकती है; किन्तु यदि उद्योग पर्याप्त रूप से विकसित न हों, तो यही जनसंख्या बेरोजगारी, अल्परोजगार एवं आजीविका-संकट का स्रोत बन जाती है।

श्रमशक्ति संरचना का विश्लेषण (Labour Force Structure)

टोंक जिले की श्रमशक्ति संरचना इसकी कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। जनगणना श्रमिकों को मुख्यतः मुख्य श्रमिक (main workers) तथा सीमांत श्रमिक (marginal workers) में, और व्यावसायिक आधार पर कृषकों, कृषि श्रमिकों, घरेलू उद्योग श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों में वर्गीकृत करती है। टोंक जिले में, राजस्थान के अधिकांश अर्ध-शुष्क ग्रामीण जिलों के अनुरूप, कार्यशील जनसंख्या का अत्यधिक भाग कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की श्रेणियों में केन्द्रित है, जबकि "अन्य श्रमिक" (जिनमें विनिर्माण, व्यापार एवं सेवाएँ सम्मिलित होती हैं) का अनुपात अपेक्षाकृत सीमित रहता है (Census of India 2011, सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर; सटीक प्रतिशत हेतु District Census Handbook, Tonk के मूल आँकड़े अपेक्षित)।

राज्य के समग्र प्रतिरूप जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर लगभग 53 प्रतिशत तथा महिला कार्य सहभागिता दर लगभग 25–26 प्रतिशत रही (MoSPI, Census 2011 आधारित) के अनुरूप टोंक जिले में भी पुरुष कार्य सहभागिता महिला कार्य सहभागिता से उल्लेखनीय रूप से अधिक होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्य सहभागिता प्रायः नगरीय क्षेत्रों से अधिक होती है, क्योंकि ग्रामीण स्त्रियाँ बड़ी संख्या में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में अंशकालिक/सीमांत श्रमिक के रूप में संलग्न रहती हैं।

सीमांत श्रमिकों का उच्च अनुपात जिले की श्रमशक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सीमांत श्रमिक वे हैं जो वर्ष में छह माह से कम कार्य पाते हैं; इनकी अधिकता मौसमी रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं अल्परोजगार का संकेत देती है जो वर्षा-निर्भर कृषि अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक परिणति है। यह श्रमशक्ति वर्ष के एक बड़े भाग में अल्प-उपयोगित अवस्था में रहती है और सैद्धांतिक रूप से गैर-कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की ओर अंतरण हेतु उपलब्ध "अधिशेष श्रम" का निर्माण करती है।

ग्रामीण-नगरीय तुलना में, ग्रामीण श्रमशक्ति प्रधानतः कृषि-केन्द्रित है, जबकि नगरीय श्रमशक्ति व्यापार, सेवा एवं सीमित विनिर्माण गतिविधियों से जुड़ी है। कौशल-आधारित श्रम की उपलब्धता जिले में सीमित है; तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों (ITI, पॉलिटेक्निक) एवं औद्योगिक कौशल विकास केन्द्रों की संख्या एवं क्षमता आधुनिक औद्योगिक आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त रही है। इसका परिणाम यह है कि जिले में **अकुशल श्रम की प्रचुरता एवं कुशल श्रम की कमी** की एक संरचनात्मक विषमता विद्यमान है।

निष्कर्षतः, श्रमशक्ति संरचना का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि टोंक जिले में श्रम की मात्रात्मक उपलब्धता तो है, किन्तु औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल, निवेश एवं आधारभूत संरचना की कमी के कारण इस श्रमशक्ति का उत्पादक औद्योगिक रोजगार में पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति दूसरी परिकल्पना कि श्रमशक्ति उपलब्ध है किन्तु उसका औद्योगिक उपयोग अपर्याप्त है की पुष्टि की दिशा में संकेत करती है।

टोंक जिले में औद्योगिक विकास (Industrial Development in Tonk)

टोंक जिले की औद्योगिक रूपरेखा को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के MSME विकास संस्थान द्वारा तैयार *Brief Industrial Profile of Tonk District* से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जो इसे "औद्योगिक रूप से पिछड़ा" (industrially backward) जिला घोषित करती है।

औद्योगिक संरचना मुख्यतः सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE) तथा कारीगर इकाइयों पर आधारित है। प्रोफाइल के अनुसार जिले में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या लगभग **8,483** (एक स्थान पर 2011-12 तक 8,778 संचयी) रही, जबकि बड़ी एवं मध्यम इकाइयों की संख्या अत्यल्प केवल लगभग **6** है (Brief Industrial Profile of Tonk District, MSME-DI)। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में अनुमानित दैनिक श्रमिक नियोजन लगभग 29,000–30,000 तथा बड़ी/मध्यम इकाइयों में लगभग 1,630 दर्ज किया गया।

उद्योगों के प्रकार की दृष्टि से जिले की इकाइयाँ कृषि-आधारित (खाद्य/खाद्य तेल), वन-आधारित, पशुपालन-आधारित, वस्त्र-आधारित, खनिज-आधारित (स्लेट पत्थर, क्वार्ट्ज़) तथा इंजीनियरिंग एवं भवन-निर्माण सामग्री से संबंधित श्रेणियों में फैली हैं (MSME-DI, Tonk)। उल्लेखनीय बड़ी/मध्यम इकाइयों में निवाई के गुनसी में स्थित नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (NEI बॉल बेयरिंग निर्माण), टोंक का स्वतंत्र भारत मिल (सूती धागा), देवली रोड पर रेडीमेड गारमेंट इकाई तथा निवाई के IID केन्द्र में दाबर इंडिया (फल-रस) एवं सिद्धार्थ पॉली सैक्स सम्मिलित हैं (MSME-DI, Tonk)। ये कुछ इकाइयाँ ही जिले के सीमित संगठित औद्योगिक आधार का प्रतिनिधित्व करती हैं।

स्थानिक वितरण की दृष्टि से औद्योगिक गतिविधि RIICO द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में केन्द्रित है, जो मुख्यतः **टोंक, निवाई (दो/अधिक क्षेत्र सहित), मालपुरा एवं देवली** में अवस्थित हैं (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation; MSME-DI, Tonk)। इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 800 से अधिक विकसित भूखंडों में से बड़ा भाग आवंटित एवं उत्पादनरत है। विशेष रूप से **निवाई** अपेक्षाकृत सुदृढ़ औद्योगिक नोड के रूप में उभरा है, जिसका एक प्रमुख कारण इसका रेलवे स्टेशन से जुड़ाव तथा जयपुर-अजमेर अक्ष पर अपेक्षाकृत बेहतर अवस्थिति है।

जिले में पहचाने गए औद्योगिक समूह (clusters) इसकी संसाधन-आधारित विशेषज्ञता को प्रकट करते हैं: टोंक का नमदा (Namda) कारीगर समूह, निवाई एवं टोंक के खाद्य-तेल समूह, देवली का स्लेट-पत्थर समूह तथा टोडारायसिंह का मूर्तिकला (पत्थर शिल्प) समूह (MSME-DI, Tonk)। देवली का स्लेट/बलुआ पत्थर तथा टोंक के सूती दरी एवं ऊनी कालीन एवं रेडीमेड गारमेंट निर्यात की दृष्टि से उल्लेखनीय रहे हैं।

इन गतिविधियों के बावजूद जिले का औद्योगिक विकास स्पष्ट रूप से सीमित है। परिवहन (विशेषकर मुख्यालय का रेल-असंबद्ध होना), सीमित उपभू-जल, बड़े पूँजी-निवेश का अभाव तथा कुशल श्रम की कमी इस सीमितता के प्रमुख कारक हैं। तुलनात्मक दृष्टि से टोंक का औद्योगिक स्तर जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर या कोटा जैसे विकसित औद्योगिक जिलों से कहीं पीछे है एक ऐसी क्षेत्रीय असमानता जो राज्य के औद्योगिक मानचित्र की केन्द्र-परिधि (core-periphery) प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करती है।

जनसंख्या, श्रमशक्ति और औद्योगिक विकास के अन्तर्सम्बन्ध (Interrelationships Core Analysis)

यह खंड अध्ययन का केन्द्रीय भाग है, जिसमें पूर्ववर्ती तीन आयामों जनसंख्या, श्रमशक्ति एवं उद्योग के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की गई है।

जनसंख्या और उद्योग

लगभग 14.2 लाख की जनसंख्या जिले के लिए एक उल्लेखनीय स्थानीय उपभोक्ता बाजार का निर्माण करती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ खाद्य, वस्त्र, निर्माण सामग्री एवं उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जो सिद्धांततः कृषि-आधारित एवं उपभोक्ता-उन्मुख उद्योगों के स्थानन हेतु बाजार-आधार प्रदान करती है (लॉश के बाजार-क्षेत्र सिद्धांत के अनुरूप)। किन्तु निर्णायक प्रश्न यह है कि यह जनसंख्या आर्थिक संपदा में रूपांतरित होती है या नहीं। टोंक के संदर्भ में, चूँकि औद्योगिक आधार दुर्बल है, अतः बढ़ती जनसंख्या की उत्पादक क्षमता अपूर्ण रूप से ही दोहित हो पाती है, और परिणामस्वरूप वही जनसंख्या आंशिक रूप से बेरोजगारी एवं बहिर्गामी प्रवास का स्रोत बन जाती है।

श्रमशक्ति और उद्योग

श्रमशक्ति उद्योग का आधारभूत उत्पादन कारक है, और टोंक में इसकी मात्रात्मक उपलब्धता औद्योगिक विकास की संभावना प्रस्तुत करती है। तथापि वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के ''श्रम-कारक'' परिप्रेक्ष्य से देखें तो केवल श्रम की मात्रा पर्याप्त नहीं; श्रम की **गुणवत्ता एवं कौशल** भी निर्णायक है। जिले में अकुशल श्रम की प्रचुरता एवं कुशल/तकनीकी श्रम की कमी आधुनिक, मूल्य-वर्धित उद्योगों के विकास को सीमित करती है। ITI, पॉलिटेक्निक एवं कौशल विकास केन्द्रों की अपर्याप्तता इस अंतराल को बनाए रखती है। इस प्रकार उपलब्ध श्रमशक्ति एवं औद्योगिक आवश्यकता के बीच एक **कौशल-असंगति (skill mismatch)** विद्यमान है।

उद्योग और रोजगार

औद्योगिक विकास का सर्वाधिक प्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक प्रभाव रोजगार संरचना के विविधीकरण में दृष्टिगोचर होता है। उद्योग कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर सकते हैं और श्रमशक्ति को प्राथमिक से द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं। टोंक के संदर्भ में लघु, कुटीर एवं MSME उद्योग विशेषकर खाद्य-तेल, खाद्य प्रसंस्करण, स्लेट-पत्थर एवं नमदा/हस्तशिल्प ग्रामीण एवं अर्ध-नगरीय क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रोजगार-माध्यम हैं, क्योंकि इन्हें अपेक्षाकृत कम पूँजी एवं स्थानीय कच्चे माल पर स्थापित किया जा सकता है। महिला श्रमशक्ति, जिसकी कार्य सहभागिता वर्तमान में निम्न है, को घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प (नमदा), खाद्य प्रसंस्करण एवं सूक्ष्म उद्यमों से जोड़ा जा सकता है।

उद्योग और नगरीकरण

औद्योगिक विकास नगरीय केन्द्रों को सशक्त करता है तथा परिवहन, आवास, बाजार एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ाता है। टोंक का निम्न नगरीकरण स्तर (लगभग 22 प्रतिशत) इस तथ्य का परिणाम भी है और कारण भी कि औद्योगिक संकेन्द्रण सीमित रहा है। केन्द्रीय स्थान सिद्धांत के अनुरूप, टोंक, निवाई एवं देवली जैसे कस्बे स्थानीय औद्योगिक-सेवा नोड के रूप में विकसित होने की क्षमता रखते हैं, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार एवं बाजार का केन्द्र बन सकें।

उद्योग और प्रवास

औद्योगिक विकास एवं प्रवास के बीच विपरीत संबंध स्पष्ट है। स्थानीय औद्योगिक अवसरों के अभाव में जिले की युवा एवं सीमांत श्रमशक्ति जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा एवं दिल्ली-NCR जैसे क्षेत्रों की ओर रोजगार-प्रेरित प्रवास करती है। टोंक का जयपुर-अजमेर अक्ष पर अवस्थित होना इस प्रवास को सुगम बनाता है एक ऐसी भौगोलिक स्थिति जो दोधारी है: यह बाजार-संपर्क का लाभ देती है, किन्तु साथ ही स्थानीय श्रम के बाहर खिंचाव को भी सुगम करती है। यदि स्थानीय औद्योगिक आधार सुदृढ़ हो, तो यही प्रवास नियंत्रित होकर क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता में परिणत हो सकता है।

समग्र विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि टोंक जिले में जनसंख्या, श्रमशक्ति एवं उद्योग एक चक्रीय अन्तर्सम्बन्ध में बँधे हैं: प्रचुर जनसंख्या एवं श्रम ⟶ सीमित औद्योगिक अवशोषण ⟶ बेरोजगारी एवं प्रवास ⟶ आर्थिक विविधीकरण का अभाव ⟶ निम्न नगरीकरण एवं निम्न आय। इस चक्र को तोड़ने की कुंजी श्रमशक्ति के कौशल-संवर्धन तथा संसाधन-आधारित विकेन्द्रित औद्योगिकीकरण में निहित है।

तालिकाएँ एवं ग्राफ (संकेतात्मक प्रारूप)

नीचे प्रस्तुत तालिकाओं में केवल प्रामाणिक रूप से सत्यापित आँकड़े सम्मिलित हैं; अन्य कोष्ठकों हेतु जिला जनगणना पुस्तिका/DIC, टोंक के मूल अभिलेख से प्रविष्टि अपेक्षित है (इन्हें "मूल स्रोत से भरा जाए" के रूप में चिह्नित किया गया है)।

तालिका 1: टोंक जिले की जनसंख्या वृद्धि (चयनित दशक)

वर्ष	कुल जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर (%)
1991	9,75,006	~21.7 (1981–91)
2001	12,11,671	~24.3 (1991–2001)
2011	14,21,326	~17.33 (2001–2011)

स्रोत: Census of India, Decadal Variation in Population; District Census Handbook, Tonk (2011)।

तालिका 2: टोंक जिले के प्रमुख जनसांख्यिकीय सूचक (2011)

सूचक	मान
जनसंख्या घनत्व	~198 व्यक्ति/वर्ग किमी
नगरीय जनसंख्या का अनुपात	~22.35%
लिंगानुपात (कुल)	~949
नगरीय लिंगानुपात	~982
साक्षरता दर	~62.46%
अनुसूचित जाति (SC)	~20.26%
अनुसूचित जनजाति (ST)	~12.54%

स्रोत: Census of India 2011, District Census Handbook, Tonk।

तालिका 3: टोंक जिले का औद्योगिक परिदृश्य (संक्षिप्त रूपरेखा के अनुसार)

मद	संख्या/मान
पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ (लगभग)	~8,483
बड़ी एवं मध्यम इकाइयाँ	~6
MSE में अनुमानित दैनिक श्रमिक नियोजन	~29,000–30,000
बड़ी/मध्यम इकाइयों में रोजगार	~1,630
RIICO औद्योगिक क्षेत्र (प्रमुख)	टोंक, निवाई, मालपुरा, देवली

स्रोत: Brief Industrial Profile of Tonk District, MSME-DI, Government of India; RIICO।

प्रमुख समस्याएँ (Major Problems)

टोंक जिले के औद्योगिक विकास के मार्ग में अनेक संरचनात्मक एवं भौगोलिक बाधाएँ विद्यमान हैं। सर्वाधिक मूलभूत बाधा बड़े पूँजी-निवेश एवं वृहत्-स्तरीय उद्योगों का अभाव है, जिसके कारण रोजगार-सृजन की क्षमता सीमित रहती है। परिवहन की दृष्टि से जिला मुख्यालय का प्रत्यक्ष रेल-संपर्क से वंचित होना भारी उद्योगों के स्थानन में एक उल्लेखनीय अवरोध है। जल संसाधन की दृष्टि से सीमित उपभू-जल एवं अर्ध-शुष्क जलवायु जल-गहन उद्योगों को हतोत्साहित करती है। मानव-संसाधन की दृष्टि से

कुशल एवं तकनीकी श्रम की कमी, निम्न (विशेषकर महिला) साक्षरता तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की अपर्याप्तता एक गंभीर सीमा है। इसके अतिरिक्त कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, महिला श्रमशक्ति का अल्प-उपयोग, MSME इकाइयों की वित्तीय समस्याएँ (CGTMSE/CLCSS के प्रति जागरूकता का अभाव, संपार्श्विक की माँग, विलंबित भुगतान जैसा कि MSME-DI रिपोर्ट में उद्योग संघों द्वारा रेखांकित किया गया) तथा युवा श्रमशक्ति का बहिर्गामी प्रवास जिले की औद्योगिक संभावना को क्षीण करते हैं।

संभावनाएँ (Potentials)

समस्याओं के बावजूद जिला अनेक भौगोलिक एवं आर्थिक संभावनाओं से युक्त है। सर्वप्रथम, जयपुर एवं अजमेर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित होना एक रणनीतिक बाजार-संपर्क लाभ है। कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था कृषि-आधारित उद्योगों विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य-तेल (निवाई एवं टोंक के विद्यमान तेल-मिल समूह इसका आधार हैं) तथा डेयरी-आधारित उद्योगों की प्रचुर संभावना प्रदान करती है। खनिज आधार (स्लेट पत्थर, क्वार्ट्ज़, फेल्सपार, सिलिका रेत) पत्थर-कटाई, टाइल एवं संबंधित संसाधन-आधारित इकाइयों को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें देवली का स्लेट समूह पहले से ही निर्यातोन्मुख है। वस्त्र एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में टोंक का नमदा, ऊनी कालीन एवं रेडीमेड गारमेंट तथा टोडारायसिंह की मूर्तिकला उल्लेखनीय हैं। महिला स्वयं-सहायता समूह आधारित सूक्ष्म-उद्यम, कौशल विकास एवं स्टार्टअप आधारित गतिविधियाँ, स्थानीय बाजार-संपर्क का लाभ तथा पर्यटन एवं सांस्कृतिक उत्पादों (जिले की समृद्ध ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत) से जुड़े उद्यम भी भविष्य की संभावनाओं के क्षेत्र हैं।

सुझाव (Suggestions)

संतुलित एवं विकेन्द्रित क्षेत्रीय विकास हेतु निम्नलिखित नीति-उन्मुख सुझाव प्रस्तुत हैं:

1. जिले में ब्लॉक-स्तर पर सुव्यवस्थित औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण कराया जाए ताकि स्थानीय संसाधन-आधार के अनुरूप उद्यम चिह्नित हो सकें।
2. कृषि-आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (तेल, डेयरी, फल-सब्जी प्रसंस्करण) को प्राथमिकता एवं प्रोत्साहन दिया जाए।
3. स्थानीय युवाओं हेतु ITI/पॉलिटेक्निक एवं उद्योग-संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए ताकि कौशल-असंगति घटे।
4. महिला श्रमशक्ति को SHG आधारित सूक्ष्म, लघु एवं घरेलू उद्योगों (नमदा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण) से जोड़ा जाए।
5. RIICO औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, जल, सड़क एवं अपशिष्ट-प्रबंधन जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए।
6. MSME इकाइयों को वित्त (CGTMSE/CLCSS के प्रति जागरूकता एवं सुगम ऋण), विपणन एवं तकनीकी (साझा परीक्षण प्रयोगशाला) सहायता प्रदान की जाए।
7. जिला उद्योग केन्द्र, टोंक की भूमिका को अधिक सक्रिय एवं उद्यमी-केन्द्रित बनाया जाए।
8. टोंक, निवाई, देवली एवं मालपुरा को सुनियोजित स्थानीय औद्योगिक नोड के रूप में विकसित किया जाए।
9. सड़क संपर्क के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ रेल-संपर्क के विस्तार की संभावना का परीक्षण किया जाए, तथा डिजिटल अवसंरचना को औद्योगिक विकास से जोड़ा जाए।
10. स्थानीय संसाधनों एवं श्रमशक्ति पर आधारित विकेन्द्रित औद्योगिक विकास मॉडल अपनाया जाए, जिससे विकास का लाभ संपूर्ण जिले में स्थानिक रूप से वितरित हो।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि टोंक जिले में जनसंख्या, श्रमशक्ति एवं औद्योगिक विकास के मध्य एक गहरा एवं चक्रीय अन्तर्सम्बन्ध विद्यमान है। जनसंख्या एक साथ श्रमशक्ति एवं उपभोक्ता बाजार दोनों प्रदान करती है, किन्तु जिले की औद्योगिक संरचना की सीमित एवं चयनित-केन्द्रित अवस्था के कारण उपलब्ध मानव संसाधन का पूर्ण एवं उत्पादक उपयोग नहीं हो पा रहा है।

अध्ययन की परिकल्पनाओं के संदर्भ में निष्कर्ष इस प्रकार हैं: प्रथम परिकल्पना कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में औद्योगिक विकास अपर्याप्त है आँकड़ों से समर्थित प्रतीत होती है, क्योंकि लगभग 14 लाख की जनसंख्या के मुकाबले बड़ी इकाइयाँ नगण्य (~6) हैं। द्वितीय परिकल्पना श्रम की उपलब्धता बनाम अपर्याप्त औद्योगिक उपयोग कृषि-प्रधान श्रम संरचना एवं कौशल-असंगति के विश्लेषण से पुष्ट होती है। तृतीय परिकल्पना औद्योगिक संकेन्द्रण का नगरीय एवं परिवहन-सुगम क्षेत्रों (टोंक, निवाई, देवली)

में केन्द्रित होना RIICO क्षेत्रों के स्थानिक वितरण से समर्थित है। चतुर्थ एवं पंचम परिकल्पनाएँ विविधीकरण की आवश्यकता तथा कौशल/निवेश/अवसंरचना से बढ़ती संभावनाएँ विश्लेषण की तार्किक परिणति हैं।

भौगोलिक दृष्टि से जिला राज्य के औद्योगिक मानचित्र की केन्द्र-परिधि असमानता का परिधीय प्रतिनिधि है। कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था से गैर-कृषि एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर क्रमिक संक्रमण ही इसकी संरचनात्मक आवश्यकता है। यदि स्थानीय संसाधनों, प्रचुर श्रमशक्ति, कौशल विकास, MSME संवर्धन एवं आधारभूत संरचना को समन्वित एवं विकेन्द्रित रूप में नियोजित किया जाए, तो टोंक जिला बेरोजगारी-प्रवास के दुष्चक्र को तोड़कर संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में अग्रसर हो सकता है।

संदर्भ सूची (References APA Style)

Census of India. (2011). *District census handbook, Tonk (Rajasthan), Part A & B*. Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs, Government of India.

Census of India. (2011). *Primary census abstract Rajasthan*. Office of the Registrar General and Census Commissioner of India.

Directorate of Census Operations, Rajasthan. (2011). *Population, decadal change and work participation tables (PCA Chapters 1 & 4)*. Office of the Registrar General and Census Commissioner of India. Retrieved from https://rajasthan.census.gov.in

MSME Development Institute, Jaipur. (n.d.). *Brief industrial profile of Tonk district*. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. Retrieved from https://dcmsme.gov.in/dips/DIPR_Tonk.pdf

Ministry of Statistics and Programme Implementation. (n.d.). *Participation in economy Women and men in India (Social statistics)*. Government of India. Retrieved from https://www.mospi.gov.in

Ministry of Panchayati Raj. (2009). *A note on the Backward Regions Grant Fund (BRGF) programme*. National Institute of Rural Development, Government of India.

Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO). (n.d.). *Industrial areas and infrastructure (Tonk district)*. Government of Rajasthan. Retrieved from https://riico.rajasthan.gov.in

Government of Rajasthan. (various years). *Rajasthan economic review & Statistical abstract of Rajasthan*. Directorate of Economics and Statistics.

Chandna, R. C. (latest edition). *Population geography*. Kalyani Publishers.

Weber, A. (1929). *Theory of the location of industries* (C. J. Friedrich, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1909).